बजट 2014-2015

वित्त मंत्री

पी. चिदम्बरम

का

भाषण

17 फरवरी, 2014

प्रस्तावना

अध्यक्ष महोदया,

मैं 2014-15 का केंद्रीय अंतरिम बजट प्रस्तुत करने जा रहा हूं।

मौजूदा आर्थिक स्थिति

जब मैं यह भाषण तैयार कर रहा था तो सोच रहा था कि यह पूरे वर्ष का नियमित बजट है या अंतरिम बजट । कई बातें दोनों में समान हैं। मसलन, हमारे लक्ष्य और वैश्विक परिप्रेक्ष्य दोनों एक समान हैं। जैसा कि मैंने पिछले वर्ष भी कहा था, कि दुनियां में जो कुछ भी हो रहा है, उससे हम अप्रभावित नहीं रह सकते हैं। चूंकि सितम्बर, 2008 से ही विश्व अर्थव्यवस्था विकासशील देशों का भाग्य निर्धारित करने में निर्णायक भूमिका निभा रही है इसलिए वैश्विक अर्थव्यवस्था और वैश्विक जोखिमों के बारे में चंद शब्द कहना उचित होगा।

2. विश्व आर्थिक विकास दर 2011 में 3.9 प्रतिशत, 2012 में 3.1 प्रतिशत तथा 2013 में 3.0 प्रतिशत रही। इन प्रतिशतों से पूरी तस्वीर साफ हो जाती है । भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदार, जो हमारे विदेशी पूंजी अंतर्वाहों का एक प्रमुख स्रोत भी है; में, संयुक्त राज्य अमरीका हाल ही में मंदी के एक लम्बे दौर से उभरा है; जापान सरकार द्वारा किए गए प्रोत्साहनों से वहाँ की अर्थव्यवस्था में अच्छे संकेत हैं; कुल मिलाकर, संपूर्ण यूरोजोन में 0.2 प्रतिशत के विकास की सूचना है; और चीन की विकास दर 2011 में 9.3 प्रतिशत से घटकर 2013 में 7.7 प्रतिशत रह गई है।

3. ग्लोबल रिस्क 2014 रिपोर्ट में 31 वैश्विक जोखिमों की बात कही गई है। इनमें से, दस सबसे बड़े जोखिमों में राजकोषीय संकट, संरचनात्मक उच्च बेरोजगारी या आंशिक बेकारी, आय असमानता, अभिशासन विफलता, खाद्य संकट और राजनीतिक एवं सामाजिक अस्थिरता हैं। जिन चुनौतियों का हम सामना कर रहे हैं, वे सभी उभरती हुई अर्थ-व्यवस्थाओं में सामान्य हैं। वर्ष 2012 और 2013 अड़चन ग्रस्त वर्ष रहे। कुछेक देश ही ऐसे थे जो इन कठिनाइयों में सिर उठाकर चल पाने में कामयाब रहे और उनमें भारत था। मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे हम इस कठिन घड़ी में भारतीय अर्थव्यवस्था को बाहर निकाल सके।

चुनौतियां और उद्देश्य

4. वित्त मंत्रालय में अपनी वापसी के कुछेक दिनों में ही, मैंने घोषणा की थी कि हमारा उद्देश्य राजकोषीय समकेन, मूल्य स्थिरता, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, विकास चक्र की बहाली, निवेश वृद्धि, विनिर्माण बढ़ाना, निर्यात को प्रोत्साहित करना, परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाना और पैट्रोलियम, विद्युत, कोयला, राजमार्ग और कपड़ा जैसे कतिपय तनावग्रस्त क्षेत्रों के सम्यक और व्यावहारिक समाधान तलाशना है।

अर्थव्यवस्था की स्थिति

दोहरे घाटे और मुद्रास्फीति

6. चलिए, अब एक अच्छी बात सुनाऊँ। 2013-14 में राजकोषीय घाटा, सकल घरेलू उत्पाद के 4.6 प्रतिशत पर नियंत्रित कर लिया जाएगा और यह उस लक्ष्मण रेखा से काफी कम है जो पिछले वर्ष मैंने खींची थी। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि चालू खाता घाटा 88 बिलियन अमरीकी डालर के पिछले वर्ष के सीएडी से भी ज्यादा बढ़ने का खतरा था। यह 45 बिलियन अमरीकी डालर तक नियंत्रित हो जाएगा। मुझे सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि वित्त वर्ष की समाप्ति तक, हम विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग 15 बिलियन अमरीकी डालर और जोड़ लेंगे। विश्लेषणों तथा रेटिंग एजेंसियों ने हमारे इस प्रयास की सराहना कई माह पूर्व की थी तथा अभी तक किसी ने इसमें कोई खामी नहीं गिनाई। उम्मीद करता हूं कि अपने एजेंडे में राजकोषीय स्थिरता को सबसे ऊपर बनाए रखा है और इस तरह घरेलू विशेषज्ञ भी सहमत होंगे कि यूपीए सरकार ने जो कहा उसे करके भी दिखाया है। आगे बढ़कर मैं सभी राजनीतिक दलों से अपील करता हूं कि मेरे साथ मिलकर शपथ लें कि हम सभी कहीं भी और कभी भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो भारत की अर्थव्यवस्था की नींव की मजबूती पर असर डाले।

7. पिछले वर्ष, जब मैंने बजट भाषण पढ़ा, थोक मूल्य सूचकांक हैडलाइन मुद्रास्फीति 7.3 प्रतिशत तथा कोर मुद्रास्फीति 4.2 प्रतिशत थी। पूरे सालभर, मुद्रास्फीति में उतार-चढ़ाव होता रहा। जनवरी, 2014 की समाप्ति पर, थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति 5.05 प्रतिशत और कोर मुद्रास्फीति 3.0 प्रतिशत रही। इसके लिए सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक ने मिलजुलकर काम किया था। हालांकि हमारे प्रयास बेकार नहीं रहे, लेकिन अभी भी काफी कुछ करना है। खाद्य मुद्रास्फीति अभी भी मुख्य चिन्ता बनी हुई है। तथापि, यह 13.6 प्रतिशत के उच्च स्तर से तेजी से घटकर 6.2 प्रतिशत रह गई।

कृषि

8. इसका हमें गर्व है कि कृषि क्षेत्र में बेहतर निष्पादन हुआ है । 2012-13 में खाद्यान्न उत्पादन 255.36 मिलियन टन हुआ था तथा चालू वर्ष में इसके 263 मिलियन टन होने का अनुमान है। गन्ना, कपास, दलहन, तिलहन और गुणवत्ता पूर्ण बीजों के उत्पादन के अनुमान नए कीर्तिमान की ओर संकेत करते हैं। 2012-13 में कृषि निर्यात 41 बिलियन अमरीकी डालर रहा, जबकि 20 बिलियन अमरीकी डालर का आयात किया गया। 2013-14 में कृषि निर्यातों के 45 बिलियन अमरीकी डालर को पार करने का अनुमान है। कृषि ऋण, मौजूदा ₹ 700,000 करोड़ के लक्ष्य को पार करते हुए ₹ 735,000 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है।

यूपीए-I की पंचवर्षीय अवधि में कृषि का सकल घरेलू उत्पाद विकास बढ़कर 3.1 प्रतिशत हो गया था और यूपीए-II के पहले चार वर्षों में यह बढ़कर 4.0 प्रतिशत बना रहा। चालू वर्ष में कृषि का सकल घरेलू उत्पाद विकास 4.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

निवेश

9. मंदी के बाद भी बचत दरें 2011-12 में 31.3 प्रतिशत तथा 2012-13 में 30.1 प्रतिशत रहीं। समनुरूपी निवेश दर का प्रतिशत क्रमशः 35.5 तथा 34.8 रहा, जो यह दर्शाता है कि खनन और विनिर्माण को छोड़कर, निवेश में कोई तीव्र गिरावट नहीं रही। यदि वृद्धिशील पूंजी आउटपुट अनुपात कमोबेश एक सा बना रहता है तो इन दो वर्षों के लिए सीएसओ द्वारा अब तक सूचित 6.7 प्रतिशत और 4.5 प्रतिशत की विकास दर से, उच्चतर विकास दर हुई होती, परंतु यह नहीं हो सका। स्पष्ट है कि परियोजनाएं वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (सीओडी) हासिल नहीं कर रही थी और कार्यान्वयन राह में और भी अनेक अड़चने हैं। साथ ही जब मैं देखता हूं कि कई परियोजनाएं लॉगजैम

के कारण असफल रह जाएंगी तो ऐसे में सरकार ने निवेश सम्बन्धी मंत्रिमंडल समिति और परियोजना निगरानी दल गठित करने के बारे में कठोर कदम उठाया। उनके द्वारा लिए गए तत्काल निर्णय के लिए उनका धन्यवाद। जनवरी 2014 के अंत तक, ₹ 660,000 करोड़ की अनुमानित लागत वाली 296 परियोजनाओं को पूर्ण करने का मार्ग प्रशस्त हुआ था।

विदेश व्यापार

10. निर्यात में तेजी से वृद्धि हुई, और यह सुधार वैश्विक व्यापार के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। वैश्विक विकास दर वर्ष 2013 की 6.1 प्रतिशत से घटकर 2013 में 2.7 प्रतिशत रह गयी है। भारत का पण्य निर्यात वर्ष 2012-13 में 300.4 बिलियन अमरीकी डालर के स्तर पर पहुंच गया था । इसमें गत वर्ष के मुकाबले 1.8 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गयी। हालांकि 2013-14 में एक निराशावादी शुरूआत हुई थी, सदन को यह सूचित करते हुए मुझे प्रसन्नता है कि वर्ष के समाप्त होने तक हमारा पण्य निर्यात 326 बिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान है, जो 6.3 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाता है। यद्यपि, आयात कम हो रहा है और यह विनिर्माण या घरेलू व्यापार के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं है। हमारा उद्देश्य एक समयावधि में सन्तुलित रूप से व्यापार के साथ निर्यात तथा आयात दोनों ही क्षेत्रों में जोरदार वृद्धि का होना चाहिए।

विनिर्माण

11. विनिर्माण भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य सेक्टर है। विनिर्माण में निवेश का घटना विशेष रूप से चिंताजनक है। परिणामस्वरूप, अब तक विनिर्माण क्षेत्र में कोई सुधार नहीं हुआ है। राष्ट्रीय विनिर्माण नीति में, यह लक्ष्य नियत किया गया है कि स.घ.उ. में विनिर्माण का हिस्सा बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर दिया जाए तथा एक दशक में 100 मिलियन नौकरियां सृजित की जाएं। दिल्ली-मुबंई औद्योगिक कॉरिडोर सहित आठ राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण अंचल घोषित किए गए हैं तथा डीएमआईसी ट्रस्ट द्वारा नौ परियोजनाएं अनुमोदित की गयी हैं। दिल्ली-मुबंई औद्योगिक कॉरिडोर से बाहर पांच राष्ट्रीय निवेश एवं विनिर्माण अंचलों को भी सिद्धान्ततया अनुमोदित किया गया है। चेन्नै व बेंगलुरू, बेंगलुरू व मुंबई और अमृतसर व कोलकाता को जोड़ने वाले तीन और कारिडोरों का प्राथमिक कार्य विभिन्न चरणों में चल रहा है। स्टील, सीमेंट, परिशोधन, विद्युत एवं इलेक्ट्रानिक्स जैसे मुख्य विनिर्माण उद्योगों में, अतिरिक्त क्षमताएं संस्थापित की जा रही हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मझौले उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं। इनमें एक सरकारी अधिप्राप्ति नीति को अधिसूचित करना, प्रौद्योगिकी केंद्रों एवं सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना करना और खादी मार्क की शुरूआत करना सम्मिलित हैं।

अवसंरचना

12. हमने अवसंरचना उद्योगों में अवसंरचना और क्षमता वर्धन को काफी प्रोत्साहन दिया है। हमने 2012-13 में और चालू वित्त वर्ष के 9 महीनों में, 29,350 मेगावाट की विद्युत क्षमता, 3,928 कि.मी. के राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत 39,144 कि.मी. की ग्रामीण सड़कें 3,343 कि.मी. के नए रेल ट्रैक और हमारे बंदरगाहों में प्रति वर्ष 217.5 मिलियन टन की क्षमता जोड़ी है। इसके अलावा, 19 तेल एवं गैस खंड अन्वेषण के लिए दिए गए तथा 7 नए हवाई अड्डों का निर्माण कार्य चल रहा है। हमने अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं के लिए अंतरण वित्तपोषण की व्यवस्था के लिए तथा बैंकिंग प्रणाली पर बढ़ते ऋण दबाव को कम करने के लिए अवसंरचना ऋण निधियों को भी सुकर बनाया है।

मुद्रा दर

13. अस्थिर वैश्विक स्थिति के चलते यू.एस. फैडरल रिजर्व द्वारा आस्ति क्रयों में कमी का संकेत मई, 2013 में मिलने से पूंजी प्रवाहों के जोखिम बढ़ गये। रुपये पर दबाव आ गया। सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और सेबी ने पूंजी

प्रवाहों को सुकर बनाने और विदेशी मुद्रा बाजार को स्थिर बनाने के लिए अनेक उपाय किए। उभरती आर्थिक अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राओं में, रुपया कम से कम प्रभावित हुआ जब दिसंबर, 2013 और जनवरी, 2014 में वास्तविक कमी हुई।

सकल घरेलू उत्पाद-गिरावट और बढ़ोत्तरी

14. माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि अर्थव्यवस्था में धीमापन 2011-12 में शुरू हुआ। सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर 2011-12 की पहली तिमाही में 7.5% थी जो नौ तिमाहियों में कम होकर 2013-14 की पहली तिमाही में 4.4 प्रतिशत रह गयी। जिन अनेक उपायों का मैंने उल्लेख किया है, उनके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। मुझे विश्वास था कि यह गिरावट रुक जाएगी और दूसरी तिमाही में विकास सुधरेगा। मैं विश्वास करता हूं कि इसके लिए मैं सही साबित हुआ हूं। 2013-14 की दूसरी तिमाही में विकास दर 4.8 प्रतिशत रही तथा संपूर्ण वर्ष के लिए विकास दर 4.9 प्रतिशत अनुमानित की गई है। इसका अभिप्राय है कि 2013-14 की तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही में विकास दर कम से कम 5.2 प्रतिशत होगी।

15. मैं विश्वास से कह सकता हूं कि अर्थव्यवस्था आज पहले दो वर्षो से अधिक स्थिर है। राजकोषीय घाटा गिर रहा है। चालू खाता घाटा नियंत्रित किया गया है, स्फीति में नरमी आयी है, तिमाही विकास दर बढ़ने की ओर अग्रसर है। मुद्रा दर स्थिर है। निर्यात बढ़ गये हैं और सैंकड़ों परियोजनाओं को फिर से चालू कर दिया गया है।

16. अध्यक्ष महोदया, यह सब कठोर परिश्रम का परिणाम है। अन्य गुरुओं के साथ-साथ, मैं मेरी माता जी और हार्वर्ड का उल्लेख करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे कठोर परिश्रम की अहमियत की सीख दी।

यूपीए कार्यकाल का विकास रिकार्ड

17. पिछले 10 वर्षों में, यूपीए सरकारों ने भारत और भारतीयों को विनम्रता पूर्वक यह अहसास कराया है कि विकास अनिवार्य है; और इसे ज्यादा से ज्यादा समावेशी और विकासोन्मुखी होना चाहिए और विकास माडल सतत रहे, तथा इसमें पर्यावरण, अन्तपीढ़ीगत साम्यता, ऋण ग्रस्तता, स्वामित्व और संसाधनों का नियंत्रण एवं वित्तपोषण, आदि जैसी चिंताओं की ओर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

18. यूपीए शासन का विकास रिकार्ड अच्छा रहा है।

19. दस वर्ष पहले, हमने 213 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन किया था। आज हम 263 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन कर रहे हैं। दस वर्ष पहले, संस्थापित विद्युत क्षमता 112,700 मेगावाट थी; और आज यह क्षमता 234,600 मेगावाट है। दस वर्ष पहले, कोयले का उत्पादन प्रति वर्ष 361 मिलियन टन था। आज हम प्रति वर्ष 554 मिलियन टन उत्पादन कर रहे हैं। दस वर्ष पहले प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 51,511 किलोमीटर लम्बी ग्रामीण सड़कें थीं, आज हमारे पास 389,578 किलोमीटर लम्बी ग्रामीण सड़के हैं। दस वर्ष पहले, शिक्षा पर केन्द्र सरकार का व्यय 10,145 करोड़ रुपए था । इस वर्ष हमने 79,451 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। दस वर्ष पहले, केन्द्रीय सरकार ने स्वास्थ्य पर 7,248 करोड़ रुपए खर्च किए। इस वर्ष यह 36,322 करोड़ रुपए खर्च करेगी। मैं बहुत से उदाहरण दे सकता हूं, परन्तु मैंने जो कहा है, वह काफी होगा।

20. अध्यक्ष महोदया, मैं नीतिगत निष्क्रियता के तर्क को नकारता हूं। जैसे कारोबार चक्र होता है, उसी तरह अर्थव्यवस्था की विकास दर के चारों तरफ भी एक चक्र होता है। पिछले 33 वर्षों में, भारत में औसत विकास दर 6.2 प्रतिशत रही है। 1992-2004 की अवधि के दौरान, सकल घरेलू उत्पाद की औसत वार्षिक दर 5.9 प्रतिशत रही। यह औसत दर से भी नीचे है। 2004-2009 के अगले पांच वर्षों की अवधि में, यह 8.4 प्रतिशत रही थी और

सीएसओ के अनुमान के अनुसार, यह 2009-2014 की अवधि में 6.6 प्रतिशत रह गई। यूपीए की दोनों सरकारों ने औसत विकास दर से अधिक दिया है।

21. पिछले 10 वर्षों में किये गए कार्य ही हमारे लिए निर्णायक होंगे ।

2013-14 का रिपोर्ट कार्ड

22. अपने सहयोगियों की ओर से मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं देश की अर्थव्यवस्था और लोगों के कल्याण के संबंध में चालू वित्तीय वर्ष में हासिल की गयी कुछ प्रमुख उपलब्धियों की बात करूँ। हम केवल अतीत की ओर ही नहीं देख रहे हैं, बल्कि हम भविष्य की ओर भी देख रहे हैं। इसलिए, मैं अपने सहयोगियों द्वारा की जाने वाली पहल कदमियों के बारे में भी बताना चाहूंगा।

विशिष्ट निर्णय

23. सरकार ने कई उल्लेखनीय निर्णय लिए हैं जिनमें साहसिक दीर्घकालीन महत्व वाले निर्णयों के रूप में सराहे गए कुछ निर्णय भी सम्मिलित हैं । चीनी पर पूरी तरह से नियंत्रण हटा लिया गया। डीजल मूल्यों में धीरे-धीरे सुधार शुरू हो गया है। रेलवे किराया एक दशक में पहली बार तर्कसंगत बनाया गया है। नए बैंक लाइसेंस जारी करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। डिस्कॉम, जो ज्यादातर रूग्ण हैं, का पुनरुत्थान केंद्रीय सहायता देकर किया जा रहा है।

एतिहासिक विधान

24. अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारम्परिक अधिनियम के अधीन 12.8 लाख भूमि पट्टे वितरित किए गए। इनका क्षेत्रफल 18.80 लाख हेक्टेयर बैठता है।

25. भूमि अर्जन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, पुनर्वास और पुर्नस्थापन अधिनियम 1.1.2014 को अधिसूचित किया गया। अंततोगत्वा दमनात्मक औपनिवेशिक कानून, 1894 का अंत हो गया।

26. 67 प्रतिशत जनसंख्या को खाद्यान्न सुनिश्चित करते हुए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया।

27. 1956 के पुराने कानूनों के स्थान पर, नया कंपनी अधिनियम आ गया है।

28. नई पेंशन प्रणाली के लिए सांविधिक आधार एवं एक सांविधिक विनियामक की स्थापना के संबंध में, पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया।

आर्थिक पहल

29. अपेक्षाकृत अधिक प्राधिकार और उत्तरदायित्व के लिए 66 कार्यक्रमों में केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं पुनः बनाई गई। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियां राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में जारी की जाएगीं। इससे राज्यों को अधिक अधिकार और उत्तरदायित्व मिलेगें। परिणामस्वरूप, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता बजट अनुमान 2013-14 में आवंटित ₹136,254 करोड़ से काफी बढ़कर 2014-15 में ₹338,562 करोड़ हो जाएगी।

30. वर्ष 2013-14 के दौरान, पब्लिक सेक्टर, उद्यम पूंजी व्यय में ₹257,641 करोड़ का एक नया रिकार्ड प्राप्त करेगी।

31. सभी स्वीकृतियों एवं अनुमोदनों की प्राप्ति के पश्चात, लगभग 50,000 मेगावाट तापीय एवं पन विद्युत क्षमता निर्माण का कार्य चल रहा है। 78,000 मेगावाट के विद्युत उत्पादन के लिए, कोयला आपूर्ति का आश्वासन दिया गया।

32. दूरसंचार, भेषज, नागर विमानन, विद्युत व्यापार संगठनों और मल्टी-ब्रांड रिटेल में अधिक निवेश जुटाने के लिए, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश नीति को उदार बनाया गया।

33. दो सेमी-कन्डक्टर वाटर फैब यूनिटों को स्थापित करने का अनुमोदन दिया गया है। यह इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर उद्योग की आधारशिला होगी।

34. ₹4,909 करोड़ के परिव्यय से, डाक विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण परियोजना 155,000 स्टेशनों में 2015 तक काम करना शुरू कर देगी।

35. कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट I ने महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। यह 180 मिलियन यूनिट विद्युत आपूर्ति कर रहा है। कलपक्कम स्थित 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रिडर रिएक्टर पूरा होने वाला है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक 10,080 मेगावाट की संस्थापित क्षमता प्राप्त करने के उद्देश्य से, सात न्यूक्लियर पावर रिएक्टरों का निर्माण कार्य चल रहा है।

36. ग्रिड संयोजित सौर ऊर्जा का लक्ष्य पार कर जाने और 1,684 मेगा वाट की क्षमता प्राप्त कर लेने के पश्चात्, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन 1.4.2013 को द्वितीय चरण में प्रवेश कर गया है। वर्ष 2014-15 के दौरान, चार अल्ट्रा मेगा सोलर प्रोजेक्ट शुरू करने का प्रस्ताव है। इनमें से प्रत्येक की क्षमता 500 मेगावाट होगी।

37 सबसे निचले स्तर पर नवोन्मेषों को संवर्द्धित करने के लिए, सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्रालय "भारत समावेशी नवोन्मेष निधि" गठित करेगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के उद्यमों की सहायता के लिए सामाजिक प्रतिलाभ मिलेगें। मैं इस निधि की संग्रह राशि के लिए 100 करोड़ का प्रारंभिक अंशदान करने का प्रस्ताव करता हूँ।

सामाजिक क्षेत्र संबंधी पहल

38. अनुसूचित जातियों के बीच उद्यमशीलता बढ़ाने तथा उन्हें रियायती वित्तपोषण उपलब्ध कराने के लिए, आईएफसीआई अनुसूचित जाति उद्यम पूंजी निधि स्थापित करेगी। इसके लिए मैं ₹ 200 करोड़ की प्रारंभिक पूंजी उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूँ। इसकी अनुपूर्ति हर वर्ष की जा सकेगी।

39. पुनः बनाई गई एकीकृत बाल विकास योजना 400 जिलों में कार्यान्वित की गयी है और 1.4.2014 से यह शेष जिलों में कार्यान्वित की जाएगी।

40. सरकार ने राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014 अनुमोदित की है। इसके बहु-विध उद्देश्य हैं जिनमें रोजगार, उत्पादकता, संरक्षण और पारिस्थिति सम्मिलित हैं।

41. गौण वनोत्पाद के विपणन के लिए एक तंत्र की शुरूआत की गई है। इस योजना को 2014-15 में जारी रखने के लिए, ₹444.59 करोड़ का बजट आबंटन किया गया है।

42. कम्युनिटी रेडियो स्टेशनों को बढ़ावा देने के लिए, ₹100 करोड़ के आबंटन से एक नई स्कीम अनुमोदित की गयी है।

43. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जन साधारण को नई प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराई हैः जिनमें जे ई टीका, जो थैलेसीमियाग्रस्त मरीजों के लिए एक नैदानिक जांच है और सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने के लिए एक मैग्नीविजुलाइजर शामिल हैं।

कुछ राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता

44 पूर्वोत्तर राज्य, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की ओर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। चालू वर्ष में आवंटित की गई निधियों के अलावा, मैं इस वष की समाप्ति से पूर्व, इन राज्यों को 1,200 करोड़ की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता राशि जारी करने का प्रस्ताव करता हूँ।

अंतरिक्ष

45 भारत मार्स आर्बिटर मिशन की स्थापना करके गिने-चुने देशों की श्रेणी में आ गया है। हमने अब प्रौद्योगिकी, क्राईयोजनिक्स, नेविगेशन, मौसम वैज्ञानी और संचार उपग्रहों के प्रेक्षेपण में क्षमता प्राप्त कर ली है। 2014-15 में अनेक फ्लाईट परीक्षणों नेविगेशनल उपग्रहों और अंतरिक्ष मिशनों की योजना है।

वायदों को पूरा करना

46. गत वर्ष, मैनें तीन वायदे किए थे और बालिका, युवा छात्र और गरीब व्यक्ति को सामने रखते हुए माननीय सदस्यों से अनुरोध किया था। महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, मैंने निर्भया निधि बनाने का वायदा किया और इस निधि में ₹1000 करोड़ आबंटित किए थे। हमने अब तक, दो प्रस्ताव अनुमोदित किए हैं। इन्हें इस निधि से सहायता मिलेगी। यह स्पष्ट करने के लिए कि यह निधि एक स्थायी निधि होगी, मैं ₹1000 करोड़ के अनुदान को व्ययपगत-भिन्न अनुदान घोषित करना चाहता हूँ। अतिरिक्त प्रस्तावों की सहायता के लिए,मैं अगले वर्ष में इस निधि में ₹1000 करोड़ की और राशि देने का प्रस्ताव करता हूँ।

47. मैंने लाखों युवकों और महिलाओं के कौशल विकास के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का दूसरा वायदा किया था और इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम को यह कार्य सौंपा था। राष्ट्रीय कौशल अधिप्रमाणन और आर्थिक पुरस्कार स्कीम अगस्त 2013 में शुरू की गई थी। यह व्यापक रूप से बहुत कामयाब रही है। अब तक, 24 सेक्टर कौशल परिषदें, 442 प्रशिक्षण भागीदार और 17 आलकन एजेंसियां, इस कार्यक्रम में शामिल हुई। 204 जॉब रोल्स को अंतिम रूप दिया गया है। 168,043 युवकों ने इस कार्यक्रम में नामांकन कराया और 77,710 प्रशिक्षुओं ने प्रशिक्षण पूरा किया। माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि मैंने इस स्कीम के लिए ₹1000 करोड़ निर्धारित किए थे। यह पूरी राशि राष्ट्रीय कौशल विकास ट्रस्ट को अंतरित कर दी जाएगी। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के इस कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए, मैं अगले वर्ष में इस ट्रस्ट को ₹1000 करोड़ की अतिरिक्त राशि अंतरित करने का प्रस्ताव करता हूँ। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने वास्तव में, जम्मू-कश्मीर में उड़ान जैसे कौशल विकास कार्यक्रम संचालित करने वाले कई मंत्रालयों के प्रयासों की प्रशंसा की है।

48. मेरा तीसरा वायदा यह था कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण स्कीम पूरे देश में लागू कर दी जाएगी। यह स्कीम मुश्किल से एक साल पुरानी है। 27 अभिज्ञात स्कीमों के अंतर्गत धनराशि फायदाग्राहियों को अंतरित की जा रही है। इसमें राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम भी शामिल है। 31.01.2014 तक, इसके जरिए कुल 54,20,114 ट्राजेंक्शन किए गए हैं और ₹628 करोड़ की राशि अंतरित की जा चुकी है। इसी तरह, ₹3,370 करोड़ की एक और राशि ₹2.1 करोड़ एलपीजी फायदाग्राहियों को अंतरित की गई है। यह स्कीम, निर्दिष्ट की गयी कठिनाइयों का समाधान लंबित होने तक फिलहाल रोक दी गई है। तथापि, मैं पुनः बताना चाहूंगा कि सरकार आधार के प्रति और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सभी आधार धारकों के बैंक खाते खोलने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध रही है। इसके अंतर्गत, अभी तक ₹57 करोड़ यूनीक नम्बर जारी किए जा चुके हैं। आधार की आवश्यकता किसे है? ये वे लोग हैं जो सबसे निचले पायदान पर हैं, गरीब हैं, प्रवासी मजदूर हैं, बेघर हैं, दबे-कुचले और बेसहारा लोग हैं। इन्हें आधार की जरूरत है और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इन्हें आधार मिले। मुझे कोई शंका नहीं है कि आगे चलकर आधार के आलोचक भी यह मानेंगे कि आधार सशक्तिकरण का एक कारगर साधन है।

अंतरिम बजट का विहंगावलोकन

आयोजना और आयोजना-भिन्न व्यय

49. अब मैं अंतरिम बजट का विहंगावलोकन दूंगा। कुछ वर्षों में, हमने बजट में सीमा से अधिक उपलब्ध कराया है। उन वर्षों में बचत अपरिहार्य रही हैं। इसके अतिरिक्त, यदि संभावना से कम विकास होता है तो राजस्व भी

संभावना से कम प्राप्त होगा। 2013-14 एक ऐसा ही वर्ष रहा। मुझे आशंका है कि हम बजटीय आयोजना व्यय को खर्च नहीं कर पाएंगे, परंतु आयोजना-भिन्न व्यय बजट में किए गए प्रावधान से थोड़ा अधिक हो जाएगा।

50. आयोजना व्यय की गति बनाये रखने के लिए, मैनें निर्णय किया है कि 2014-15 में आयोजना व्यय को उसी स्तर पर बनाये रखा जाए जिस स्तर पर इसका बजट प्रावधान 2013-14 में किया गया था। मैनें आयोजना व्यय के लिए ₹555,322 करोड़ का प्रावधान किया है। मुझे सदन को यह बताते हुए वर्ष हो रहा है कि जो मंत्रालय/विभाग यूपीए सरकार के मुख्य फ्लैगशिप कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं, उन सभी को पर्याप्त निधियां प्रदान की गई हैं। वर्ष 2014-15 में, मैने वर्ष के संशोधित अनुमानों को ध्यान में रखे बिना, निम्नलिखित सभी को बजट अनुमान 2013-14 की तुलना में, या तो उसके बराबर अथवा उससे अधिक धनराशि उपलब्ध करायी हैः

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	- ₹3,711 करोड़
जनजातीय कार्य मंत्रालय	- ₹4,379 करोड़
आवास और गरीबी उपशमन मंत्रालय	- ₹6,000 करोड़
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	- ₹6,730 करोड़
पंचायती राज मंत्रालय	- ₹7,000 करोड़
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	- ₹15,260 करोड़
महिला और बाल विकास मंत्रालय	- ₹21,000 करोड़
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	- ₹33,725 करोड़
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	- ₹67,398 करोड़
ग्रामीण विकास मंत्रालय	- ₹82,202 करोड़

रेलवे

51. मेरे सहयोगी रेल मंत्री ने कुछेक दिन पहले रेल बजट प्रस्तुत किया। रेलवे को बजटीय सहायता बजट अनुमान 2013-14 में ₹26,000 करोड़ से बढ़ाकर 2014-15 में ₹29,000 करोड़ कर दी गई है। रेलवे को बाजार उधार और सरकारी निजी भागीदारी योजनाओं के माध्यम से भारी संसाधन जुटाने की आवश्यकता है। प्रस्ताव है कि रेल परियोजनाओं के लिए निधियां जुटाने हेतु नई लिखतें और नये तंत्र चिन्हित किये जाएं।

अनुसूचित जाति उप-योजना और जनजातीय उप-योजना

महिलोन्मुखी बजट और बाल बजट

52. माननीय सदस्यों को यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैं अनुसूचित जाति उप-योजना के लिए ₹48,638 करोड़ रुपए और जनजातीय उप-योजना को ₹30,726 करोड़ करने का प्रस्ताव करता हूँ। वे यह जानकर भी प्रसन्न होंगे कि महिलोन्मुखी बजट के लिए ₹97,533 करोड़ रुपए और बाल बजट हेतु ₹81,024 करोड़ रुपए रखे गए हैं।

53. मुझे विश्वास है कि शिकायत के लिए कोई कारण नहीं होगा। यदि कहीं कोई कमियां है, तो उन्हे नियमित बजट प्रस्तुत करते समय दूर किया जा सकता है। समग्र संसाधनों के भीतर आवंटनों में आवश्यक संशोधन करने के लिए व्यय बजट में काफी गुंजाइश है।

54. वर्ष 2014-15 में आयोजना-भिन्न व्यय ₹12,07,892 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। इसमें से, खाद्य, उर्वरक एवं ईंधन के लिए दी जाने वाली सब्सिडी पर व्यय ₹2,46,397 करोड़ रुपए होगा। यह 2013-14 में रखे गये ₹2,45,452 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान से थोड़ा सा अधिक है। ईंधन सब्सिडी हेतु ₹65,000 करोड़ का

प्रावधान किया है। इस वर्ष, हमने 2012-13 की चतुर्थ तिमाही से ₹45,000 करोड़ की राशि का उपयोग किया और इस वर्ष की चतुर्थ तिमाही से अगले वर्ष में ₹35,000 करोड़ रुपए का राशि का प्रयोग करेंगे। संपूर्ण देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्रियान्वित करने की हमारी सरकार की सुदृढ़ और अडिग प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, खाद्य सब्सिडी हेतु ₹115,000 करोड़ रुपए की राशि आबंटित की गयी है।

रक्षा

55. रक्षा के लिए आवंटन बजट अनुमान 2013-14 में ₹2,03,672 करोड़ रखा गया था। इसे 10 प्रतिशत बढ़ाकर 2014-15 में ₹2,24,000 करोड़ रुपए किया गया है।

एक रैंक एक पेंशन

56. माननीय सदस्य, रक्षा सेवाओं की लम्बे समय से की जी रही एक रैंक-एक पेंशन (ओरओपी) की मांग से अवगत हैं। यह एक भावात्मक विषय है। इसके कानूनी निहितार्थ हैं और इससे अत्यंत सावधानी से निपटना होगा। यूपीए सरकारों के कार्यकाल के दौरान, रक्षा सेवाओं के लिए लागू होने वाले पेंशन नियम 2006, 2010 एवं 2013 में तीन अवसरों पर अधिसूचित किए गए हैं। परिमामस्वरूप, चार अर्थात हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार और सूबेदार मेजर रेंकों में (दूर की जा रही कुछ विसंगतियों की शर्त पर) 2006 से पहले और 2006 के बाद सेवानिवृत्त होने वालों के बीच अन्तर समाप्त हो गया है। सिपाही और नायक के रैंकों में छोटा सा अन्तर तथा मेजर और उससे ऊपर के रैंकों में अन्तर अभी बना हुआ है। हमें एक युवा लडाकू बल की आवश्यकता है, हमें युवा जवानों की आवश्यकता है और हमें युवा अधिकारियों की आवश्यकता है। हमें रक्षा सेवाओं में केवल सीमित वर्षों के लिए कार्यरत रहे व्यक्तियों की देख-भाल भी करनी है। इसलिए, सरकार ने अंतिम उपाय करते हुए प्रत्येक रैंक में सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों की पेंशन में अन्तर को समाप्त करने का निर्णय लिया है। मुझे यह सूचित करते हुए खुशी हो रही है कि सरकार ने रक्षा बलों के लिए एक रैंक एक पेंशन के सिद्धांत को मान लिया है। यह निर्णय वित्त वर्ष 2014-15 से भविष्यलक्षी प्रभाव से कार्यान्वित किया जाएगा। इसके लिए 2014-15 में ₹500 करोड़ की आवश्यकता का अनुमान है। यूपीए सरकार की प्रतिबद्धता की पूर्ति हेतु, मैं इसी चालू वर्ष में रक्षा पेंशन खाते के लिए ₹500 करोड़ की राशि अंतरित करने का प्रस्ताव करता हूँ।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल

57. केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की क्षमता बढ़ाने और उन्हें अत्याधुनिक उपकरण और प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए, ₹11,009 करोड़ की लागत से आधुनिकीकरण योजना अनुमोदित की गई है। चालू वित्त वर्ष और अगले वर्ष के लिए निधियों की व्यवस्था की गई है।

वित्तीय क्षेत्र

बैंकिंग

58. माननीय सदस्यो, मैंने फरवरी, 2013 के बजट भाषण में वित्तीय क्षेत्र विषयक, जो उद्घोषणाएं की थी, वे कार्यान्वित कर दी गयी हैं या की जा रही हैं। 2014-15 में, मैं सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पूंजी निवेशन के लिए ₹11,200 करोड़ आबंटित करने का प्रस्ताव करता हूँ। इन बैंकों का 8,023 शाखाएं खोलने का लक्ष्य था। अभी तक, 5,207 शाखाएं खोली गयी हैं, और प्रत्येक शाखा में एटीएम लगाने के अपने लक्ष्य के नजदीक हैं। भारतीय

महिला बैंक का शुभारंभ 19.11.2013 को किया गया। ग्रामीण आवास निधि को ₹6,000 करोड़ और शहरी आवास निधि को ₹2000 करोड़ उपलब्ध कराए गए।

59. अनर्जक आस्तियों के बढ़ने से बैंक दबाव में हैं। बैंकरों ने मुझे आश्वस्त किया है कि जैसे ही अर्थव्यवस्था में सुधार आएगा वे अनर्जक आस्तियों को नियंत्रित करने, अधिक ऋणों की वसूली करने और अधिक सकारात्मक तुलन पत्र तैयार करने में सफल होंगे।

60. इस बीच, मैं सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को लोगों तक पहुँचाने के लिए बैंकों द्वारा कठिन समय में दी गई सेवा को नहीं भुला सकता हूँ। इस वर्ष, बैंक कृषि ऋण के ₹700,000 करोड़ का लक्ष्य पार कर लेंगे। इसलिए 2014-15 में इसके लिए, मैं ₹8,00,000 करोड़ का लक्ष्य निश्चित करता हूँ। माननीय सदस्यों को याद होगा कि 2006-07 में ब्याज सहायता योजना शुरू की गई थी। समय से पहले ऋण अदा करने वाले किसानों के लिए इसमें 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता और 3 प्रतिशत का प्रोत्साहन देने की व्यवस्था है। इस प्रकार, कृषि ऋणों पर प्रभावी ब्याज दर 4 प्रतिशत तक कम की गई है। अभी तक, इस स्कीम के अंतर्गत ₹23,924 करोड़ की राशि जारी की गयी है। मैं 2014-15 में इस स्कीम को जारी रखने का प्रस्ताव करता हूँ।

अल्पसंख्यक समुदायों को ऋण

61. एक दशक पहले, भारत अल्पसंख्यक बहुल 121 जिलों में अल्पसंख्यकों के 14,15,000 बैंक खाते थे। मार्च, 2013 की समाप्ति पर, उनके 43,52,000 खाते हैं और ऋण राशि ₹4,000 करोड़ से बढ़कर ₹66,500 करोड़ हो गई है। दिसम्बर 2013 की समाप्ति पर, सम्पूर्ण देश में अल्पसंख्यक समुदायों को ₹211,451 करोड़ के ऋण दिए गए है।

स्वयं सहायता समूह

62. दस वर्ष पहले, केवल 9,71,182 स्वयं सहायता समूहों को ऋणों के लिए बैंकों से जोड़ा गया था। दिसंबर, 2013 के अंत में, 41,16,000 महिला स्वयं सहायता समूहों को ऋण दिया गया और बकाया ऋण राशि ₹36,893 करोड़ थी।

शिक्षा ऋण

63. दस वर्ष पहले, केवल कुछ हजार विद्यार्थियों, जो अच्छी तरह जुड़े हुए थे, ने शिक्षा के लिए ऋण प्राप्त किए। दिसंबर 2013 की समाप्ति पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में 25,70,254 खाते विद्यार्थी ऋण के थे और ऋण की बकाया राशि ₹57,700 करोड़ थी।

64. माननीय सदस्यों को याद होगा कि मेरे पूर्ववर्ती श्री प्रणब मुखर्जी ने 2009-10 के बजट में 1.4.2009 के बाद संवितरित शिक्षा ऋण के संबंध में केंद्रीय ब्याज सब्सिडी सहायता योजना शुरु की थी। इसके तहत सरकार ने अध्ययन और उसके कुछ बाद तक की अवधि के लिए ब्याज का भार स्वय उठाया। इस स्कीम से उधार लेने वाले विद्यार्थियों और उनके परिवारों में खुशी की लहर आयी। तथापि, जिन विद्यार्थियों ने 31.3.2009 के पहले ऋण लिया था, उन विद्यार्थियों के बीच भेदभाव होने की बात मेरे ध्यान में आयी। वे अध्ययन की अवधि के दौरान ब्याज चुकाने के लिए संघर्ष करते रहे, और उसके बाद भी ऋण चुकता करते रहे। मेरे विचार से वे कुछ राहत के पात्र हैं। इसलिए मैं, 31.3.2009 से पहले लिए गए और 31.12.2013 को बकाया सभी शिक्षा ऋणों के लिए ऋणस्थगन अवधि का प्रस्ताव रखता हूँ। 31.12.2013 की स्थिति के अनुसार, बकाया ब्याज की देनदारियों को सरकार चुकाएगी परन्तु उधारकर्ता को 1.1.2014 के बाद की अवधि के लिए ब्याज चुकाना होगा। अनुमान है कि इससे लगभग 9 लाख उधारकर्ता विद्यार्थियों को लगभग ₹2,600 करोड़ का फायदा होगा। मैं वर्तमान वित्त वर्ष में ही निधियां देना चाहता हूँ। तदनुसार ₹2,600 करोड़ की राशि केनरा बैंक को अंतरित की जाएगी। यह बैंक प्राधिकृत सीएसआईएस बैंकर है। इस स्कीम के ब्योरे की घोषणा जल्द कर दी जाएगी।

बीमा

65. इस वर्ष अर्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान करने हेतु 10,000 या इससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों में जीवन बीमा निगम ने 1,252 कार्यालय खोले हैं और चार पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंश कंपनियों ने 1,849 कार्यालय खोले हैं। वे अपने लिए निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निरन्तर आगे बढ़ रही हैं।

वित्तीय बाजार

66. भारतीय वित्तीय बाजार की गहरी पैठ बनाने के लिए, अनेक उपायों की परिकल्पना की गई है। वे हैं-

- एडीआर/जीडीआर स्कीम का व्यापक पुनरुद्धार और निक्षेपागार प्राप्तियों की संभावना बढ़ाना;
- रुपया मूल्यवर्गित कारपोरेट बांड बाजार को उदार बनाना;
- विदेशी मुद्रा जोखिम से पूरी तरह अपनी रक्षा करने हेतु भारतीय कंपनियों को समर्थ बनाने के लिए मुद्रा व्युत्पन्न बाजार को गहन और सुदृढ़ बनाना;
- प्रत्येक व्यष्टि की वित्तीय आस्तियों के लिए एक रिकार्ड रखना;
- भारतीय बांडों में निवेश करने के इच्छुक अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए मंजूरी और व्यवस्थापन को सुचारु बनाना।

पण्य व्युत्पन्न बाजार

67. माननीय सदस्यों को नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड में हुए भुगतान संकट के बारे में याद होगा। इस विषय के वित्त मंत्रालय में अंतरण के बाद एनएसईएल को अधिकार में लेने और यह सुनिश्चित करने, कि, वित्तीय बाजार के अन्य विनियमित खण्डों के लिए कोई बकाया भुगतान का संकट न हो, तुरन्त कार्रवाई की गई। मैं, पण्य व्युत्पन्न बाजार के विनियामक ढ़ांचे को सुदृढ़ करने के लिए वायदा संविदा (विनियमन) अधिनियम का प्रस्ताव करता हूँ।

मुख्य लंबित विधेयक

68. मुझे यह बताते हुए खेद है कि बीमा विधि (संशोधन विधेयक) और प्रतिभूति विधि (संशोधन विधेयक) संसद द्वारा कुछ ऐसे कारणों के चलते पारित नहीं किये गये जिनका इन विधेयकों की मैरिट से कुछ लेना देना नहीं है।

लोक ऋण प्रबंध अभिकरण

69. बजट भाषण 2011-12 में की गई घोषणा के अनुपालन में, सरकार, लोक ऋण प्रबंध अभिकरण विधेयक के लिए तैयार है। पूर्वनिर्णय का पालन करते हुए, गैर-सांविधिक लोक ऋण प्रबंध अभिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह 2014-15 में कार्य शुरु कर सकेगा।

भावी योजना

70. अध्यक्ष महोदया, अब मैं भावी कार्य योजना की रूपरेखा प्रस्तुत करता हूँ।

71. मुझे आश्चर्य है कि कितने लोग इस बात को जानते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था अपने सकल घरेलू उत्पाद के आकार के सन्दर्भ में विश्व में 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। यह अधिक तर्कसंगत है कि अगले तीन दशकों में, भारत का सामान्य स.घ.उ. देश को अमेरिका और चीन के बाद तीसरे स्थान पर ले जाएगा। जिस प्रकार विकसित देशों की किस्मत आज उभरती अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करतीं है, चीन और भारत की किस्मत, भविष्य में शेष विश्व पर, महत्वपूर्ण प्रभाव डालेगी। इसलिए हमारी जिम्मेदारी न केवल हमारे लिए है अपितु पूरे विश्व के लिए है ताकि हम अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रख सकें।

72. जिन लक्ष्यों को हमने अपने लिए निर्धारित किया है उनके प्रति यूपीए सरकार की दृष्टि स्पष्ट है। मैंने उन लक्ष्यों को हासिल करने के कार्यों हेतु कदम उठाया है, जिन्हें आज सरकार के द्वारा किया जाना है। मैं ऐसे दस कार्यों को अभिचिन्हांकित करने का अनुरोध करता हूँ:-

(i) **राजकोषीय सुदृढ़ीकरणः** हमें 2016-17 तक राजकोषीय घाटे के स.घ.उ. के 3 प्रतिशत का लक्ष्य हासिल करना और हमेशा उससे से नीचे के स्तर पर बने रहना है।

(ii) **चालू खाता घाटाः** चूंकि कुछ और वर्षों तक हमें प्रत्येक वर्ष चालू खाता घाटा उठाना होगा। इसका वित्तपोषण विदेशी निवेश से ही हो सकता है, चाहे वह एफडीआई या एफआईआई अथवा ईसीबी या किसी अन्य प्रकार का विदेशी अंतर्वाह ही क्यों न हो। अतः विदेशी निवेश के किसी विपथन की कोई गुंजाइश नहीं है।

(iii) **मूल्य स्थिरता और विकासः** विकासशील अर्थव्यवस्था में हमें स्वीकार करना है कि जब हमारा लक्ष्य अधिक विकास है तो मुद्रास्फीति का स्तर थोड़ा कम होगा। मौद्रिक नीति बनाते समय, भारतीय रिजर्व बैंक को मूल्य स्थिरता और विकास के बीच संतुलन बनाना होगा।

(iv) **वित्तीय क्षेत्र में सुधारः** वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग की जिन सिफारिशों में किसी विधायी परिवर्तन की जरूरत नहीं है, उन्हें तत्काल कार्यान्वित किया जाए और अन्य सिफारिशों के लिए विधान पारित करने हेतु हमें एक समय सारणी बनानी चाहिए।

(v) **अवसंरचनाः** हमें अपनी अवसंरचना पुनः बनानी चाहिए और नई अवसंरचना की बहुत बड़ी मात्रा जोड़ी जानी चाहिए। प्रत्येक जांचा-परखा माडल अपनाना चाहिए, पीपीपी माडल का और व्यापक प्रयोग किया जाना चाहिए। दीर्घावधिक निधियों और निवेशों के पूलिंग हेतु नए वित्तीय ढ़ांचे सृजित किए जाने चाहिए।

(vi) **विनिर्माणः** हमें विनिर्माण और विशेषकर निर्यात के लिए विनिर्माण पर ध्यान देना होगा। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर लगने वाले सभी केंद्रीय अथवा राज्य कर माफ किए जाए या उनसे छूट दी जाए। मैं यह प्रस्ताव भी करता हूँ कि एक न्यूनतम टैरिफ संरक्षण हो ताकि वस्तुओं को भारत में आयात करने की बजाय, भारत में उनके विनिर्माण के लिए प्रोत्साहन दिया जाए।

(vii) **सब्सिडियांः** सीमित संसाधनों को स्वीकारते हुए और उन संसाधनों पर अनेक दावों के चलते हमें उन सब्सिडियों का चयन करना चाहिए जो वास्तव में जरूरी हैं और उन्हें सर्वथा जरूरतमंदों को ही दें।

(viii) **शहरीकरणः** हमारे शहर बेकाबू हो जाएंगे और शायद रहने योग्य न रहें यदि हम अपने शहरों में अपकर्ष का समाधान नहीं करते। शहरों के पास भूमि के रूप में संपत्ति है। शहर धन सृजित भी करते हैं। वह धन अभिशासन के नए माडल के चलते शहर के पुनर्निर्माण हेतु संसाधनों में लगाया जाना चाहिए।

(ix) **कौशल विकासः** सरकार की प्राथमिकताओं में कौशल विकास को माध्यमिक शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षा, संपूर्ण स्वच्छता और सबके लिए स्वास्थ्य के साथ स्थान मिलना चाहिए।

(x) **राज्यों और केन्द्र के बीच जिम्मेदारी वहन करनाः** राज्यों के पास फ्लैगशिप कार्यक्रम क्रियान्वित करने की वित्तीय लागत का युक्तिसंगत अनुपात वहन करने की वित्तीय गुंजाइश है और उन्हें स्वेच्छा से ऐसा करना चाहिए ताकि केन्द्र सरकार रक्षा, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग और दूरसंचार जैसे क्षेत्रों के लिए अधिक संसाधन आवंटित कर सके जो इसकी अनन्य जिम्मेवारी है।

राजस्व

वस्तु एवं सेवा कर तथा प्रत्यक्ष कर संहिता

73. राजस्वों का अत्यंत महत्व है। राजस्व का सबसे अच्छा स्रोत कर हैं और इसके लिए हमें आधुनिक कर विधियों की जरूरत है। मेरी चिंता यह है कि अभी तक हम वस्तु एवं सेवा कर लागू करने में सफल नहीं हो पाए हैं। अब, मैं इस सवाल का जवाब आप पर छोड़ता हूँ कि जब कर सुधार होने को था तो वे कौन थे जिन्होंने इस वस्तु एवं सेवा कर को लागू होने से रोका। हमने प्रत्यक्ष कर संहिता भी तैयार कर ली है। यह कम से कम अगले 20 वर्षों तक हमारे काम आएगी। पार्टीलाइन और दलगत भावना से ऊपर उठकर स्वस्थ सार्वजनिक बहस के लिए, मैं इस संहिता को वेबसाइट में डालना चाहता हूँ। मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से अपील करता हूँ कि वे 2014-15 में वस्तु एवं सेवा कर विधियों और प्रत्यक्ष कर संहिता को पारित करने का संकल्प लें।

वैज्ञानिक शोधों का वित्तपोषण

74. हमारी सरकार वैज्ञानिक सरोकारों का समर्थन, वैज्ञानिक शोधों को प्रोत्साहन और वैज्ञानिक अनुप्रयोगों एवं नवोन्मेषों का समर्थन करती रही है। आय कर अधिनियम में वैज्ञानिक शोधों पर होने वाले व्यय के लिए कटौती की अनुमति का उल्लेख है, किंतु यह प्रत्यक्ष वित्तपोषण तक ही सीमित है। हमने वैज्ञानिक शोधों के वित्तपोषण की एक नई अवधारणा दर्शित की है। इसलिए, मैं अनुसंधान वित्तपोषण संगठन की स्थापना करने का प्रस्ताव करता हूँ। यह संगठन प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया द्वारा चयनित शोध परियोजनाओं तक का वित्तपोषण करेगा। इस संगठन को दिया जाने वाला अंशदान कर लाभ के लिए पात्र होगा। इसके लिए विधायी परिवर्तनों की जरूरत होगी जिन्हें नियमित बजट में शामिल किया जा सकेगा।

अपतटीय खाते

75. भारतीयों द्वारा धारित अवैध अपतटीय खातों पर काफी बहस होती रही है। ऐसे खातों की जांच 2011 में शुरु की गई थी। संबंधित देशों से साक्ष्य मिलने में कई बाधाओं के बावजूद, सरकार, कामयाब रही और वैकल्पिक तरीकों और विशेष प्रयासों के जरिए, 67 मामलों में सूचना प्राप्त की गई तथा कर देयता अवधारित करने और शास्ति अधिरोपित करने संबंधी कार्रवाई अधिकार क्षेत्रों में जारी है। 17 अन्य मामलों में जानबूझकर कर चोरी करने वालों पर अभियोजन शुरू किये गए हैं। नो-टैक्स या लो-टैक्स मामलों में भारतीय कम्पनियों द्वारा कथित रूप से धारित खातों की और जांच की जा रही है।

कर दरों में बदलाव

76. परिपाटियों को ध्यान में रखते हुए, मैं कर विधियों में बदलाव संबंधी कोई घोषणा नहीं करना चाहता हूँ। फिर भी, मौजूदा आर्थिक हालात कुछ ऐसे जरूरी दख़ल की मांग करते हैं जिनके लिए नियमित बजट तक नहीं रुका जा सकता है। विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र को तत्काल प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है। इसलिए, मैं कुछ अप्रत्यक्ष कर दरों में निम्नलिखित परिवर्तनों का प्रस्ताव करता हूँ:

(i) पूंजीगत वस्तुओं और उपभोक्ता टिकाऊ भिन्न वस्तुओं में वृद्धि को प्रोत्साहन देने के लिए, मैं 30.6.2014 तक की अवधि के लिए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की अनुसूची के अध्याय 84 और अध्याय 85 के अन्तर्गत आने वाली सभी वस्तुओं पर उत्पाद-शुल्क 12 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ। नियमित बजट प्रस्तुत करते समय इन दरों की समीक्षा की जा सकेगी।

(ii) ऑटोमोबाइल उद्योग, अप्रत्याशित नकारात्मक वृद्धि दर्शा रहा है। इसे राहत देने के लिए, मैं 30.6.2014 तक की अवधि के लिए नीचे लिखित उत्पाद-शुल्क घटाने का प्रस्ताव करता हूँ:

छोटी कार, मोटर साइकिल, स्कूटर और

वाणिज्यिक वाहन - 12 से 8 प्रतिशत

एसयूवीज - 30 से 24 प्रतिशत

बड़ी और मिड-सेग्मेंट कारें - 27/24 प्रतिशत से 24/20 प्रतिशत

परिणामस्वरूप, मैं चेसिस और ट्रेलरों पर उत्पाद-शुल्क में उचित कटौती करने का प्रस्ताव करता हूँ। नियमित बजट प्रस्तुत करते समय इन दरों की समीक्षा की जा सकती है।

(iii) मोबाइल हैंडसेटों के घरेलू उत्पादन (जो गिर गया है) को प्रोत्साहित करने तथा आयातों पर निर्भरता कम करने (जो बढ़ गये हैं) के लिए, मैं मोबाइल हैंडसेटों की सभी श्रेणियों हेतु उत्पादन शुल्कों की नई दरों का प्रस्ताव करता हूँ। ये दरें सेनवेट क्रेडिट के चलते 6 प्रतिशत और सेनवेट क्रेडिट के बगैर 1 प्रतिशत होंगी।

(iv) साबूनों और रंगीन रसायनों का घरेलू उत्पादन प्रोत्साहित करने के लिए, मैं खाद्य भिन्न ग्रेड औद्योगिक तेल और इसके भाग, वसीय अम्लों और वसीय अल्कोहलों पर सीमा-शुल्क ढ़ाचें को युक्तिसंगत कर 7.5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करता हूँ।

(v) विनिर्दिष्ट सड़क निर्माण मशीनरी का घरेलू उत्पादन प्रोत्साहित करने के लिए, मैं ऐसी आयातित मशीनरी पर लगने वाली सीवीडी से छूट समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूँ।

(vi) करेंसी नोटों के मुद्रण के लिए प्रतिभूति कागज के प्रयोग किए जाने वाले स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु, मैं बैंक नोट पेपर मिल इंडिया-प्राइवेट लिमिटेड द्वारा आयातित पूंजी माल पर 5 प्रतिशत रियायती सीमाशुल्क प्रदान करने का प्रस्ताव रखता हूँ।

77. मैं निम्नलिखित मामलों में सेवा कर से राहत देने का भी प्रस्ताव करता हूँ।

(i) नकारात्मक सूची के साथ पठित वित्तीय अधिनियम, 2012 में 'कृषि उपज' की परिभाषा के कारण धान का भण्डारण और भांडागारण को सेवा कर से छूट प्राप्त थी, परन्तु चावल को नहीं। यह भिन्नता कुछ हद तक कृत्रिम है। अतः, मैं चावल की लदाई-उतराई,पैकिंग,भंडारण और भांडागारण को सेवा कर से छूट देने का प्रस्ताव करता हूँ।

(ii) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अनुरोध किया है कि कोर्ड ब्लड बैंक द्वारा दी जा रही सेवाएं भी स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं हैं। इसलिए ये सेवा कर-मुक्त होनी चाहिए। मैं यह अनुरोध स्वीकार करने का प्रस्ताव करता हूँ।

उपर्युक्त बदलावों के संबंध में अधिसूचनाएं आज ही जारी कर दी जाएंगी।

बजट अनुमान

78. मैं, अब, 2014-15 के लिए बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूँ।

79. चालू वित्त वर्ष 4.6 प्रतिशत राजकोषीय घाटे (4.8 प्रतिशत की निर्णायक रेखा से नीचे) और 3.3 प्रतिशत राजस्व घाटे के संतोषजनक स्तर पर समाप्त होगा।

80. मैंने, की गई प्रगति से प्रोत्साहित होकर, 2014-15 में प्राप्तियों और व्यय की बजटीय व्यवस्था की है। राजकोषीय घाटा 4.1 प्रतिशत होगा, जो नये राजकोषीय समेकन द्वारा नियत लक्ष्य से कम रहेगा। राजस्व घाटा 3.0 प्रतिशत होने का अनुमान है।

81. आयोजना व्यय का अनुमान ₹ 5,55,322 करोड़ है। आयोजना-भिनन व्यय ₹12,07,892 करोड़ होना अनुमानित है।

निष्कर्ष

82. अध्यक्ष महोदया, जीन ड्रेज़ और अमृत्य सेन ने उल्लेख किया है कि ''भारत ही वह पहला गैर-पश्चिमी और विश्व में प्रथम गरीब देश है जो शासन के लोकतांत्रिक उद्देश्यों के लिए प्रतिबद्ध है''। लोकतंत्र विविधता को स्वीकरता है, विसम्मति का सम्मान करता है, बहस को प्रोत्साहित करता है और चुने हुए प्रतिनिधियों के मार्फत राजनीतिक फैसले करता है। शासन का विकल्प ना तो लोकप्रियतावाद है, ना बहुसंख्यावाद और ना ही व्यक्तिवाद है।

83. हमारे शासन के तौर-तरीके 10 वर्षों में 140 मिलियन आबादी को गरीबी से उबारने में आड़े नहीं आये। इसी को मैं यूपीए सरकारों की महानतम उपलब्धि मानता हूँ, और हमें इस उपलब्धि पर गर्व है।

84. इन दस वर्षों में नॉर्थ ब्लॉक में रहते हुए, मैने अच्छा और बुरा दोनो ही समय देखे। लेकिन मैने कभी भी जवाहरलाल नेहरू के सपनों के भारत पर अपनी आस्था नही डिगने दी। सुनील खिलनानी के शब्दों में कहें, तो ''लोकतंत्र, धार्मिक-सहिष्णुता, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक बहुलवाद जैसे विविध मूल्यों को समर्पित एक आधुनिक राज्य बनाने के लिए हर संभव सहयोग देने'' उद्देश्य पर अपनी आस्था नहीं डिगने दी। यही वह विश्वास है जो मुझमें हमेशा बना रहेगा। मुझे यकीन है कि भारत के लोग यह जिम्मेदारी उन्हीं हाथों में सौपेंगे जो समता द्वारा नियंत्रित सत्ता को धारण करे।

महान सन्त थिरुवल्यूवर के शब्दों में कहें तोः

*''**वेलअनरु वेन्ड्री थरुवदु मन्नवन, कोलदुगू कोडत्तु इन्न**''*

(भाले-बरछें नहीं, बल्कि सिर्फ समता और बराबरी से युक्त सत्ता ही राजा को असली विजय दिलाती है)।

85. अध्यक्ष महोदया, इन शब्दों के साथ, मैं यह अंतरिम बजट सदन को सौंपता हूँ।